साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार, 27 जनवरी-02 फरवरी 2025 वर्ष-10, अंक-41
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

बजट से पहले किसानों को मोदी का तोहफा | कच्चे जूट का एमएसपी 5,650 रुपए क्विंटल निर्धारित

जूट की एमएसपी में 315 रुपए प्रति क्विंटल सरकार ने किया इजाफा

भोपाल। जागत गांव हमार

बजट से पहले मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने (सीसीईए) ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। 2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट (टीडी-3 ग्रेड) का एमएसपी 5,650 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसमें 315 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने दावा किया है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान कच्चे जूट की एमएसपी में लगभग ढाई गुणा की वृद्धि की जा चुकी है। किसान आंदोलन के बीच जूट उगाने वाले किसानों को यह सौगात देना अहम माना जा रहा है। कच्चे जूट का एमएसपी 2025-26 सीजन के लिए 5,650 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इससे उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 66.8 प्रतिशत का रिटर्न सुनिश्चित होगा। साल 2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट का घोषित एमएसपी सरकार द्वारा बजट 2018-19 में घोषित उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुरूप है।

सिफारिशों को स्वीकारा

केंद्र यह फैसला कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया है। सरकार ने कहा कि 2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए एमएसपी में पिछले सीजन की तुलना में 315 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों के दौरान, सरकार ने लगभग ढाई गुणा (2.35 गुणा) की वृद्धि करते हुए कच्चे जूट के लिए एमएसपी को 2014-15 में 2,400 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2025-26 में 5650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2014-15 से 2024-25 की अवधि के दौरान जूट उत्पादक किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि 1300 करोड़ थी, जबकि 2004-05 से 2013-14 की अवधि के दौरान भुगतान की गई राशि 441 करोड़ थी।

जूट एमएसपी की घोषणा

केंद्र सरकार ने कच्चे जूट की एमएसपी 2014-15 के 2,400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2025-26 के लिए 5,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जो 2.35 गुना वृद्धि है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि 40 लाख किसान परिवारों की रोजी-रोटी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जूट उद्योग पर निर्भर है। जूट मिलों और जूट के व्यापार में लगभग 4 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। पिछले साल 1.7 लाख किसानों से जूट खरीदा गया था। जूट उत्पादन में 82 प्रतिशत किसान पश्चिम बंगाल से हैं, जबकि असम और बिहार में जूट उत्पादन में 9-9 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

बंगाल में सबसे अधिक उत्पादन

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश के करीब 40 लाख किसान परिवारों की आजीविका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जूट उद्योग पर निर्भर है। जूट मिलों और जूट के व्यापार में लगभग 4 लाख को रोजगार मिलता है। वहीं, पिछले साल 1 लाख 70 हजार किसानों से जूट खरीदा गया था। साथ ही देश में सबसे अधिक 82 फीसदी जूट किसान पश्चिम बंगाल से हैं जबकि असम और बिहार में जूट उत्पादन में 9-9 फीसदी की हिस्सेदारी है। जेसीआई मूल्य समर्थन परिचालन करने के लिए केन्द्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में काम करना जारी रखेगी। वहीं, ऐसे परिचालनों में होने वाली हानि की पूरी क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी।

सूर्य योजनाः 10 प्रतिशत कीमत लेकर सोलर पंप देगी मप्र सरकार

दो लाख किसानों को सोलर खरीद पर 90 फीसदी सब्सिडी

-123 ग्रामों के खेत में सिंचाई के लिए नर्मदा जल पहुंचेगा

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में फसलों की सिंचाई के लिए व्यवस्था करने के लिए नदी जोड़ो परियोजना के साथ ही कई सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1042.24 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उन्होंने 982.59 करोड़ लागत की महेश्वर जानापाव उद्वहन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 2 लाख से ज्यादा किसानों को सोलर पंप खरीद के लिए 90 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाएगी।

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के पर्यटन और पवित्र नगर महेश्वर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। यहां उन्होंने महेश्वर-जानापाव उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1042.24 करोड़ लागत के कुल 27 योजनाओं का लोकार्पण और

सोलर पंप पर सब्सिडी

मुख्यमंत्री ने किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में लगभग 2 लाख अस्थायी पंप धारक किसानों को 03 हॉर्स पावर से लेकर 7.5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप खरीदने में सरकार सहायता प्रदान करेगी। इसमें किसानों को केवल 10 फीसदी राशि का भुगतान करना होगा। जबकि, बाकी राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

नर्मदा के पानी से होगी सिंचाई

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 982 करोड़ 59 लाख की महेश्वर जानापाव उद्वहन सिंचाई परियोजना के पूर्ण होने पर खरगोन जिले की महेश्वर, धार जिले की पिथमपुर एवं इंदौर जिले की मऊ तहसील के कुल 123 ग्रामों के किसानों के खेत में सिंचाई के लिए नर्मदा का जल पहुंचेगा। इससे इन गांवों के किसानों का कृषि उत्पादन बढ़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

बंद होंगी शराब की दुकानें

मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में नई योजना तैयार की गई है। इसके तहत प्रदेश की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण सहित हर क्षेत्र में समर्थ बनाया जाएगा। उन्होंने शराब बंदी के लिए नीतिगत निर्णय का जिक्र करते हुए कहा कि हमने तय किया है कि राज्य धीरे-धीरे शराबबंदी की तरफ बढ़े इस क्रम में निर्णय किया गया है। पहले चरण में 17 धार्मिक नगर हैं, जहां शराब दुकानें बंद की जाएंगी।

इन प्रोजेक्ट का शिलान्यास- लोकार्पण

शिलान्यास के 7 कार्यों की लागत 994.72 करोड़ रुपए एवं लोकार्पण के 20 कार्यों की लागत राशि 47.52 करोड़ शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महेश्वर जानापाव माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना लागत 982.59 करोड़ का शिलान्यास किया। रिटेनिंगलवाल निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक 7 राज्य वित्त आयोग कार्य लागत 0.27 करोड़ और वाटर बॉडी परियोजना इंटेकवेल के पास नर्मदा तट का सुदृढ़ीकरण एवं पुनरुद्धार-अमृत 2.0 कार्य लागत 0.25 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास किया।

मप्र के कई जिलों के किसानों को होगा फायदा

बागवानी फसलों के लिए बनेंगी अलग मंडियां

अब किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार ऐसी मंडियों की सौगात देने जा रही है, जहां वे उचित कीमत पर बागवानी फसलों की उपज बेच सकेंगे। राज्य सरकार इसके लिए 11 जिलों में अलग से उद्यानिकी उपज मंडी बनाएगी। राज्य सरकार के फैसले को अमल में लाने के लिए उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने मंत्रालय में उद्यानिकी बोर्ड के साथ बैठक की। मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि बागवानी फसल उगाने वाले किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। इस उद्देश्य से राज्य सरकार अलग से उद्यानिकी फसल उपज मंडी बोर्ड बनाने पर काम कर रही है। मंत्री ने बताया कि ये 11 बागवानी कृषि उपज मंडी-इंदौर, बुरहानपुर, शाजापुर, मंदसौर, उज्जैन, बदनावर, रतलाम, नीमच, भोपाल, जावरा और शुजालपुर में शुरू होंगी। इन मंडियों में एक लाख टन से ज्यादा बागवानी फसलों की आवक होती है। पहले चरण में बोर्ड बनावर उद्यानिकी फसलों की बिक्री के लिए अलग से परिसर बनाएगा।

किसान सीधे बेच सकेंगे फसल - उद्यानिकी मंत्री ने संचालक उद्यानिकी, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड प्रबंध संचालक एमपी एग्रो और विशेषज्ञों की टीम को एक महीने में सर्वे का काम पूरा कर सलाहकार बोर्ड के सामने रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। मंत्री ने बताया कि उद्यानिकी उपज मंडियां पूरी हाईटैक होंगी, जिनमें किसान सीधे उपभोक्ताओं को अपनी फसल बेच सकेंगे। यह व्यवस्था बिचौलियों से मुक्त होगी।

नई मंडियों में होंगी सुविधाएं

प्रदेश में अभी मप्र कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अधीन मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया है। इनमें कृषि और उद्यानिकी का फसलों की खरीद-बिक्री एक ही परिसर में की जाती है। प्रदेश की 25, कृषि उपज मंडी समिति है इनमें फल-सब्जियों के विक्रय के लिये 174 मंडियां लिस्टेड हैं। नई व्यवस्था लागू होने पर फल-फूल, सब्जी फसल के लिए अलग नए मंडी परिसर बनाए जाएंगे। प्रस्तावित मंडियों में ग्रेडिंग, सोर्टिंग, पैकिंग, पैकहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चैन, भंडारण आदि सुविधाएं भी होंगी।

नए आवेदन होंगे शुरू

मंत्री ने विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए बैठक में अफसरों से उद्यानिकी विभाग को हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए नए ऑनलाइन आवेदन मंगाने के लिए कहा है। साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी सरल बनाने के लिए कहा है। ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिल सके। वहीं, संचालक उद्यानिकी प्रीति मैथिल ने कहा कि उद्यानिकी विभाग के पोर्टल से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

पोटाश ने मारी छलांग: यूरिया में आत्मनिर्भर होगा भारत

डीएपी की बिक्री गिरते ही अन्य खादों की बढ़ी डिमांड

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में खादों की बिक्री बढ़ गई है। सभी खादों की बिक्री का रिकॉर्ड देखें तो इस साल 7.3 परसेंट की उछाल दर्ज की गई है। सभी खादों की बिक्री का यह आंकड़ा 526 लाख टन के आसपास है। यूरिया की बिक्री में भी अच्छी वृद्धि देखी गई है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 6.4 प्रतिशत की तेजी है। पिछले साल यूरिया जहां 282 लाख टन बिकी थी। वहीं इस वित्त वर्ष में 31 दिसंबर तक 300 लाख टन तक बिक्री हो चुकी है। एक सरकारी आंकड़े में बिक्री की रिपोर्ट दी गई है। दूसरी ओर डीएपी खाद की बिक्री में कमी आई है और 12.7 परसेंट की गिरावट के साथ 86 लाख टन खाद बिकी है। हालांकि म्यूरेट ऑफ पोटाश की बिक्री 31 परसेंट बढ़ी है और यह 17 लाख टन के आसपास है। कॉम्प्लेक्स खाद की बिक्री में 27 परसेंट का उछाल है और यह 122 लाख टन दर्ज की गई है। कॉम्प्लेक्स खाद में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर आते हैं। सरकार ने पहले 2025 तक भारत को यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा था और अधिक बिक्री के बावजूद इसके आयात पर अंकुश लगा दिया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में यूरिया का आयात पहले नौ महीनों के दौरान 43.16 लाख टन दर्ज किया गया, जबकि एक साल पहले यह 60.71 लाख टन था। यानी 28.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। पूरे वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान यूरिया का रिकॉर्ड आयात 98.28 लाख टन रहा था। अप्रैल-दिसंबर के दौरान कुल खादों का आयात भी 18.4 प्रतिशत घटकर 120.54 लाख टन रह गया, जिसमें कॉम्प्लेक्स खादों का आयात 17.71 लाख टन से 16.1 प्रतिशत घटकर 14.85 लाख टन रह गया। डीएपी का आयात 50.47 लाख टन से 19.1 प्रतिशत घटकर 40.82 लाख टन रह गया। लेकिन, एमओपी का आयात 15.3 प्रतिशत बढ़कर 21.71 लाख टन हो गया।

नैनो डीएपी पर अधिक फोकस

सरकार अब नैनो डीएपी के लिए भी वैसा ही प्रयास करने की योजना बना रही है जैसा उसने नैनो यूरिया के मामले में किया था, ताकि फसल की पैदावार को प्रभावित किए बिना फॉस्फेटिक खाद की खपत भी कम हो। सभी खादों का उत्पादन 1.6 प्रतिशत बढ़कर 391.62 लाख टन हो गया, जिसमें यूरिया 232.02 लाख टन, डीएपी 31.5 लाख टन, कॉम्प्लेक्स 81.94 लाख टन, एसएसपी 40.57 लाख टन और अमोनियम सल्फेट 5.59 लाख टन शामिल हैं।

डीएपी की सब्सिडी में बढ़ोतरी

यूरिया सब्सिडी 98,258.74 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जबकि पोटाश और फॉस्फोरस के लिए यह 40,990.67 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो कुल मिलाकर बजट में आवंटित 1,64,000 करोड़ रुपए का 84.9 प्रतिशत है। सरकार ने अभी तक संशोधित अनुमान की घोषणा नहीं की है, जिसमें इस वित्त वर्ष में दो बार डीएपी पर सब्सिडी में बढ़ोतरी के कारण बिक्री मूल्य 1,350 रुपए/बैग पर बनाए रखने के लिए बजट में रिवीजन होगा।

सब्जियों का उत्पादन चार गुना बढ़ाएग, शहरों को 50 फीसदी आपूर्ति मिलेगी

विदेशों में सब्जी और बागवानी फसलें उगाई जा रहीं और क्वालिटी के साथ ही बंपर उपज देखने को मिल रही

घटती कृषि भूमि, जल संकट का समाधान हाइड्रोपोनिक्स

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में अगले पांच साल में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती तेजी से बढ़ने वाली है। क्योंकि, इसके लिए कम भूमि के साथ ही 90 फीसदी कम पानी की जरूरत होती है। यह पॉलीहाउस में की जाती है घटती हुई कृषि योग्य भूमि, जल संकट और शहरीकरण जैसी चुनौतियों का सॉल्यूशन देती है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक किसानों तक पहुंचा रही दिग्गज एग्रीटेक सॉल्यूशन कंपनी ब्रिओ हाइड्रोपोनिक्स के फाउंडर और सीईओ जय कुमार भट्ट ने एक विशेष बातचीत में इसके फायदे और चुनौतियों पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि विदेशों में इस तकनीक से सब्जी और बागवानी फसलें खूब उगाई जा रही हैं और अच्छी क्वालिटी के साथ ही बंपर उपज देखने को मिल रही है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से सब्जियों और फलों की खेती विदेशों में तेजी से बढ़ रही है और अब यह तकनीक भारत में तेजी से विकसित हो रही है। भारत में जिस तरह से इस तकनीक को अपनाया जा रहा है यह स्थिति अगले पांच साल में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से सब्जियों का उत्पादन 4 गुना बढ़ जाएगा। शहरों में 50 फीसदी से अधिक फसलों की आपूर्ति हाइड्रोपोनिक फार्म्स से होगा।

5 साल में खेती का 8 फीसदी हिस्सा होगी हाइड्रोपोनिक्स

2030 तक हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती का दायरा भारत और विश्व में तेजी से बढ़ने की संभावना है। बदलती पर्यावरणीय स्थिति, जल की कमी, शहरीकरण और हाई क्वालिटी वाली जैविक उपज की बढ़ती मांग को देखते हुए यह तकनीक कृषि का भविष्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि देश में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती 2030 तक कुल कृषि क्षेत्र का 5-8 फीसदी हिस्सा हथिया लेगी। ग्लोबल मार्केट ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है। 2022 में ग्लोबल हाइड्रोपोनिक्स बाजार करीब 12-15 बिलियन डॉलर का था। अनुमान है कि 2030 तक यह 20-25 फीसदी की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 50-60 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा।

भारत में इसलिए बढ़ेगी तकनीक

उपभोक्ता अधिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हो रहे हैं। यह स्थिति जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग की वजह बन रही है। जबकि शहरों में छोटी जगह पर अधिक उत्पादकता देने के लिए हाइड्रोपोनिक्स एक आदर्श तकनीक बन रही। केंद्र की योजनाएं, जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और पर्यावरण-अनुकूल कृषि से इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है। कई स्टार्टअप्स और कृषि तकनीकी कंपनियां हाइड्रोपोनिक्स में निवेश कर रही हैं।

90 फीसदी तक पानी बचाने में कारगर तकनीक

सीईओ ने कहा कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती करने पर सर्वाधिक सकारात्मक असर पर्यावरणीय पर देखने को मिलेगा। इस तकनीक से खेती में 50-70 फीसदी तक कम पानी का इस्तेमाल होता है। कुछ मामलों में तो 90 फीसदी तक पानी की बचत देखी गई है। इसके अलावा के मिट्टी क्षरण और कीटनाशकों के इस्तेमाल से बचाव होगा और प्रदूषण रहित और टिकाउ खेती हो सकेगी। शहरी क्षेत्रों में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। भारत के शहरी इलाकों में वर्टिकल फार्म्स की स्थापना हो रही है और इसमें उनकी कंपनी ब्रिओ हाइड्रोपोनिक्स लोगों की मदद कर रही है। मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, और चेन्नई में ताजा उपज की मांग भी बढ़ती देखी जा रही है।

संभावनाएं और चुनौतियां

सीईओ जय कुमार भट्ट ने बताया कि हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती को अपनाने के लिए युवा ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन, इसके लिए ट्रेनिंग और ढांचे को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए उनकी कंपनी भी किसानों और युवा उद्यमियों को हाइड्रोपोनिक तकनीक में प्रशिक्षित कर रही है। जबकि, सरकार को भी इस ओर ध्यान देना होगा। इससे कई कृषि आधारित स्टार्टअप्स की संख्या में तेजी आएगी। देश के 50,000 से अधिक किसानों और उद्यमी इस तकनीक से खेती में जुड़ सकते हैं।

मप्र सहित देश के 28 राज्यों में ही गधे बचे

गधे पालने पर केंद्र सरकार देगी 50 लाख, गधों की संख्या में 60 फीसद कमी

भोपाल। जागत गांव हमार

क्रीम-साबुन जैसे कॉस्मेटिक आइटम बनाने में गधी के दूध का महत्व किसी से छिपा नहीं है। मेडिसिनल वैल्यू को देखते हुए अब बात गधी के दूध को फूड आइटम में शामिल करने की भी हो रही है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए को पत्र भी लिख चुका है। अभी हाल ही में सार्वजनिक तौर पर बाबा रामदेव ने भी गधी का दूध पीकर उसे स्वादिष्ट बताया था। लेकिन परेशानी वाली बात ये है कि गधों की संख्या लगातार घट रही है। गधों की उन्नत नस्ल मालधारी गधे तो और भी कम हो गए हैं। अब तो बस उंगलियों पर गिनने लायक ही बचे हैं। इसी को देखते हुए केन्द्र सरकार गधों की संख्या बढ़ाने, नस्ल सुधार और पालन के लिए योजना चला रही है। योजना के तहत गधे पालने के लिए 50 लाख रुपए तक की वित्तीय मदद दी जा रही है। साथ ही बाजार और तकनीकी सहायता भी दी जा रही है।

एनएलएम योजना

साल 2015 में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना शुरू की गई थी। शुरू में इस योजना के तहत 25 से 50 लाख रुपए की रकम सब्सिडी के तहत दी जाती थी। खासतौर पर गधों की बात करें तो इस योजना के तहत गधों का ब्रीडिंग सेंटर, नस्ल सुधार और गधा पालन पर जोर दिया जा रहा है। सरकार लागत का 50 फीसद सब्सिसडी के तौर पर दे रही है।

देश में ये है बचे हुए गधों की संख्या

एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में हुए पशुगणना के आंकड़ों पर जाएं तो देश में गधों की कुल संख्या 1.23 लाख है। गधों की सबसे ज्यादा संख्या जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र , गुजरात, कर्नाटक और आंध्रा प्रदेश में है। इन राज्यों में गधों की संख्या एक लाख के आसपास है। देश के 28 राज्यों में ही गधे बचे हैं। उसमे भी कई राज्य ऐसे हैं जहां गधों की संख्या दो से लेकर 10 के बीच है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का अफसरों से आह्वान

एनडीडीबी महिलाओं के लिए दुग्ध क्षेत्र में रोजगार के बढ़ाएं अवसर

तिलहन के क्षेत्र में भी काम हो रहा, सरसों-तिलहन उत्पादन को बढ़ाने किसानों को और मुहैया कराएं सुविधाएं

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज डेयरी और इससे संबंधित क्षेत्रों में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और इसकी सहायक संस्थाओं द्वारा की जा रही महत्वपूर्ण गतिविधियों पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने एनडीडीबी द्वारा प्रस्तावित नयी गतिविधियों की समीक्षा की और इन्हें मिशन मोड में आगे ले जाने के लिए मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि एनडीडीबी वर्षों से सहकारिता के माध्यम से डेयरी के क्षेत्र में अपनी सहायक संस्थाओं के साथ किसानों की आजीविका को सुधारने के प्रयास में जुड़ी हुई है और कृषि के क्षेत्र में उनका काम काफी सराहनीय है। उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि इन योजनाओं को सभी संबंधित मंत्रालय और विभाग, एनडीडीबी के साथ मिलकर उचित योजना, समझौता ज्ञापन इत्यादि करें और उस पर समय में काम को शुरू करें। शिवराज ने विभाग के अधिकारियों से कहा कि नियमित संयुक्त बैठक करें। महिलाओं के लिए दुग्ध क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाएं। एनडीडीबी के माध्यम से 5 लाख महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। एनडीडीबी सहकारिता के साथ मिलकर काम कर रहा है। एनडीडीबी, एफपीओ के माध्यम से भी काम कर रहा है। इसमें और क्या और कैसे अच्छा कर सकते हैं इस पर ध्यान दें। एनडीडीबी तिलहन के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। सरसों के उत्पादन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने और उन्हें सुविधाएं देने के लिए क्या कर सकते हैं। इस पर भी ध्यान देना होगा।

किसानों की भलाई करे

कृषि मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे पाम ऑयल मिशन की वैल्यू चैन में एनडीडीबी सहभागिता करे। इसके अलावा राज्यों के साथ मिलकर सरसों के किसानों की भलाई के लिए काम करे, जैसे कि सरसों खरीद आदि। बैठक में जानवरों के लिए हरे चारे की उपलब्धता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सूखे चारे का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, चारा व्यर्थ ना जाए। चारा बीजों की उपलब्धता बढ़ाने और सहकारिता के माध्यम से इसका विस्तार करने को लेकर भी बात हुई।

किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस

एनडीडीबी फसल अवशेषों का कुशल प्रबंधन करने में भी काम करे। साथ ही, किसानों और उपभोक्ताओं के बीच भाव का अंतर कम करने के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि एनडीडीबी के सफल ब्रांड के माध्यम से उपभोक्ता फल और सब्जी खरीदते हैं, जिसमें टमाटर, आम, शहद और मधुमक्खी पालन आदि के क्षेत्र में एनडीडीबी काम कर रहा है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे संबद्ध क्षेत्रों में काम करना चाहिए जो कि किसानों की आय बढ़ाने में अत्यंत सहभागी हो सकता है। साथ ही एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ संभावित गतिविधियों और वर्तमान में किए जा रहे कामों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

राज्य सरकार के अधिकारियों की भागीदारी की जरूरत होगी

बाजार में गेहूं, चना, चावल-सरसों की कीमत एमएसपी से अधिक

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कृषि मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में रबी की बुआई की प्रगति, मौसम की स्थिति, राष्ट्रीय कीट सर्वेक्षण प्रणाली (एनपीएसएस) के माध्यम से कीट सर्वेक्षण, कृषि उत्पादों के आयात और निर्यात सहित मार्केटिंग से संबंधित कई मुद्दे पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि मुद्दों पर वह स्वयं साप्ताहिक बैठक करने के अलावा, वह समय-समय पर कृषि मंत्रियों के स्तर पर राज्य सरकारों के साथ भी बैठकें करेंगे। उन्होंने अधिकारियों से भी कहा कि इन मुद्दों पर राज्य सरकारों के साथ लगातार जुड़े रहें, क्योंकि जमीनी स्तर पर मुद्दों को संबोधित करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों की भागीदारी की जरूरत होगी।

कृषि मंत्री ने फसलों की दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि 17 जनवरी 2025 तक कुल बोया गया क्षेत्र 640 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल की इसी अवधि के 637.49 लाख हेक्टेयर की तुलना में 2.51 लाख हेक्टेयर अधिक है। समग्र फसल कवरेज और फसल की स्थिति पिछले साल की तुलना में बेहतर है। रबी टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) की बुआई चल रही है और आज तक टीओपी फसलों की बुआई पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक है। गेहूं (0.46 फीसदी), सरसों (0.14 फीसदी), सोयाबीन (0.25 फीसदी) की मंडी कीमतें सप्ताह-दर-सप्ताह बढ़ी हैं। जबकि अरहर (1.22 फीसदी), चावल (1.20फीसदी) चना (0.67 फीसदी), आलू (6.34 फीसदी) और टमाटर (6.79 फीसदी) की मंडी कीमतों में सप्ताह-दर-सप्ताह गिरावट आई है। फिलहाल बाजार में गेहूं, चावल, चना, सरसों और तिल की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ज्यादा मिल रही है।

अब तक खरीदी गई 43 लाख 47 हजार मीट्रिक टन से अधिक धान

भोपाल। जागत गांव हमार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक 6 लाख 68 हजार 654 किसानों से 43 लाख 47 हजार 206 मीट्रिक टन धान की खरीदी उपार्जन केन्द्रों में हो चुकी है। धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए और धान ग्रेड-ए का 2320 रुपए है। किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में अभी तक 8267 करोड़ 1 लाख रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है। खरीदी गई धान में से 39 लाख 66 हजार 473 मीट्रिक टन उपार्जित धान का परिवहन किया जा चुका है। कुल 12 लाख 55 हजार 412 मीट्रिक टन धान मिलर्स को भेजी जा चुकी है।

प्रदेश के बालाघाट में 5 लाख 49 हजार 929, कटनी 4 लाख 11 हजार 821, सतना 4 लाख 1 हजार 192, जबलपुर 3 लाख 80 हजार 556, रीवा 3 लाख 48 हजार 552, सिवनी 3 लाख 1 हजार 904, मण्डला 2 लाख 2 हजार 118, शहडोल 2 लाख 186, पन्ना 1 लाख 79 हजार 343, मैहर 1 लाख 69 हजार 726, नर्मदापुरम 1 लाख 66 हजार 265, सिंगरौली 1 लाख 46 हजार 819, उमरिया 1 लाख 29 हजार 814, सीधी 1 लाख 29 हजार 352, अनूपपुर 98 हजार 706, मऊगंज 98 हजार 311, दमोह 82 हजार 963, डिंडोरी 77 हजार 604, नरसिंहपुर 77 हजार 542, रायसेन 64 हजार 850, बैतूल 47 हजार 495, सीहोर 42 हजार 514, सागर 19 हजार 223, छिन्दवाड़ा 12 हजार 959, भिंड 2 हजार 769, विदिशा 1546, शिवपुरी में 1469 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है।

कर्नाटक को मदद का दिया भरोसा

कृषि मंत्री अभी हाल में कर्नाटक दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बैंगलुरू में राज्य के कृषि, ग्रामीण विकास और राजस्व मंत्री के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में शिवराज सिंह ने राज्य में कृषि योजनाओं, ग्रामीण विकास के कार्यों, राजस्व से जुड़ी गतिविधियों और भारत सरकार की योजनाओं पर मंत्रियों और अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक होती है आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति लेकिन हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, जनकल्याण की राजनीति करते हैं। हमारे देश में संघीय लोकतंत्र है, हमारा मकसद है, राज्य सरकार को हम भारत सरकार की योजनाओं के तहत भरपूर सहयोग करें।

कृषि और ग्रामीण विकास पर मेहरबान होगी सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार का 2025-26 के लिए बजट 1 फरवरी को पेश होगा। इस बजट में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। क्योंकि, इस बार नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ ही खेती में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस हो सकता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के विकास भी बजट में प्रमुखता हासिल कर सकता है। क्योंकि, दोनों ही क्षेत्र किसान, मजदूर और महिला वर्ग से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण 1 फरवरी को आम बजट 2025-26 पेश करने वाली हैं। यह उनका लगातार 8वां बजट होगा। इस बार के बजट में अनुमान है कि सरकार ग्रामीण विकास के लिए कृषि सेक्टर को दिया जाने वाला बजट बढ़ा सकती है। इसके अलावा सरकार मध्य वर्ग, किसान, महंगाई और रोजगार पर सबसे ज्यादा फोकस करेगी। किसानों को फसल का वाजिब दाम दिलाने से जुड़े कदम उठाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार कृषि विकास के लिए बजट बढ़ा सकती है। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार इस बार कृषि और उससे जुड़े कार्यों के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर सकती है। पिछला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया था, जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। उससे पहले कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.47 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया था।

ग्रामीण विकास के लिए बढ़ेगा बजट

केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास पर खास ध्यान है। ऐसे में इस क्षेत्र के लिए भी सरकार बजट में इजाफा कर 2.70 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक राशि का प्रावधान कर सकती है। पिछली बार यानी 23 जुलाई 2024 को पेश किए गए बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

जल चक्र में अपेक्षा से अधिक बढ़ रहे हैं मानवीय हस्तक्षेपः नासा

नासा के वैज्ञानिकों ने लगभग 20 सालों का अवलोकन करके पाया कि दुनिया भर में जल चक्र तेजी से बदल रहा है। इनमें से अधिकांश खेती जैसी गतिविधियों के कारण हैं, इनका कुछ इलाकों में पारिस्थितिकी तंत्र और जल प्रबंधन पर प्रभाव पड़ सकता है। शोध पत्र में शोधकताज़ के हवाले से कहा गया कि आंकड़ों के आधार पर यह स्थापित किया गया है कि दुनिया भर में जल चक्र में मानवीय हस्तक्षेप हमारी सोच से कहीं अधिक बढ़ गया है। जल चक्र में बदलाव अधिकांश खेती जैसी गतिविधियों के कारण हैं, इनका कुछ इलाकों में पारिस्थितिकी तंत्र और जल प्रबंधन पर प्रभाव पड़ सकता है।

शोध पत्र में नासा गोडार्ड के वैज्ञानिक के हवाले से कहा गया है कि बाढ़ के लिए बुनियादी ढांचे को डिजाइन करना या शुरुआती चेतावनी प्रणालियों के लिए सूखे के संकेतक विकसित करना जैसे जल प्रबंधन अभ्यास अक्सर इस धारणा पर आधारित होते हैं कि जल चक्र केवल एक निश्चित सीमा के भीतर ही उतार-चढ़ाव पैदा करता है।

शोध में कहा गया है कि यह अब कुछ क्षेत्रों के लिए सही नहीं हो सकता है। यह शोध जल संसाधनों में तेजी से हो रहे बदलावों का आकलन करने और स्थायी संसाधन प्रबंधन की योजना बनाने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए एक मार्गदर्शक मानचित्र के रूप में काम करेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ये बदलाव सबसे ज्यादा हो रहे हैं।

जल चक्र पर मानवजनित प्रभावों का एक उदाहरण उत्तरी चीन है, जो लगातार सूखे का सामना कर रहा है। लेकिन कई क्षेत्रों में वनस्पति पनपना जारी है, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उत्पादक भूजल भंडारण से अधिक पानी पंप करके अपनी भूमि की सिंचाई करना जारी रखा गया है। इस तरह के परस्पर संबंधित मानवीय हस्तक्षेप अक्सर वाष्पोत्सर्जन और अपवाह जैसे अन्य जल चक्र चर पर जटिल प्रभाव डालते हैं।

शोध के मुताबिक, शोधकर्ताओं ने जल चक्र में तीन विभिन्न प्रकार के बदलावों पर गौर किया, पहला, प्रवृत्ति, जैसे कि भूजल भंडार में पानी की कमी, दूसरा, मौसमी बदलाव, जैसे कि साल के आरंभ में ही सामान्य वृद्धि का मौसम शुरू हो जाना या बर्फ का समय से पहले पिघल जाना और तीसरा, चरम घटनाओं में बदलाव, जैसे कि बाढ़ का अधिक बार आना। वैज्ञानिकों ने 2003 से 2020 तक नासा के कई अलग-अलग उपग्रह ïतों से रिमोट सेंसिंग से आंकड़े एकत्र किए, जिसमें बारिश के आंकड़ों के लिए ग्लोबल प्रीसिपिटेशन मेजरमेंट मिशन सैटेलाइट, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव से मिट्टी की नमी का डेटासेट और स्थलीय जल भंडारण के आंकड़ों के लिए ग्रेविटी रिकवरी और क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट शामिल है।

शोध के मुताबिक, शोधकर्ताओं ने वनस्पति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर सैटेलाइट उपकरण के उत्पादों का भी उपयोग किया।

शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया कि यह शोध सैटेलाइट के आंकड़ों के विश्लेषण पर क्षमताओं को विकसित करने में टीम के कई सालों के प्रयासों को जोड़ता है, जिससे पूरे ग्रह में महाद्वीपीय जल प्रवाह और भंडारण का सटीक रूप से अनुकरण करने में मदद मिलती है। अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि भविष्य में दुनिया भर के जल चक्र का अनुकरण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पृथ्वी प्रणाली मॉडल

को मानवीय गतिविधियों के चल रहे प्रभावों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया जाना चाहिए।

अधिक आंकड़े बेहतर मॉडल के साथ, उत्पादक और जल संसाधन प्रबंधक समझ सकते हैं और प्रभावी ढंग से योजना बना सकते हैं कि उनकी स्थानीय जल स्थिति का न्यू नार्मल कैसा दिखता है।

दुनिया भर में ताजे पानी के स्तर में अचानक आई भारी गिरावटः नासा और जर्मन उपग्रहों से प्राप्त अवलोकनों का उपयोग करते हुए, वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम को इस बात के सबूत मिले है कि मई 2014 से धरती पर मीठे या ताजे पानी की कुल मात्रा में अचानक गिरावट आई है और तब से यह कमी लगातार बनी हुई है। शोधकर्ताओं ने शोध में कहा है कि यह बदलाव इस बात का संकेत दे रहा है कि पृथ्वी के महाद्वीप सूखे चरण में प्रवेश कर चुके हैं।

शोध के मुताबिक, साल 2015 से 2023 तक के उपग्रह मापों से पता चला है कि धरती में जमा मीठे या ताजे पानी की औसत मात्रा, जिसमें झीलों और नदियों जैसे तरल सतही पानी, साथ ही भूमिगत जलभृतों का पानी शामिल है। साल 2002 से 2014 तक के औसत स्तरों से 1,200 क्यूबिक किमी से कम थी। सूखे के समय सिंचाई की जानी वाली खेती में बढ़ोतरी के साथ-साथ, खेतों और शहरों को भूजल पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है, जिससे भूमिगत जल आपूर्ति में गिरावट का चक्र शुरू हो जाता है। मीठे पानी की आपूतिज़ ठप हो जाती है, बारिश और बर्फ्बारी उन्हें फिर से भरने में कामयाब नहीं होती हैं और प्िऊर पानी के लिए और अधिक भूजल पंप किया जाता है। साल 2024 में प्रकाशित पानी की कमी को लेकर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, उपलब्ध पानी में कमी से किसानों और समुदायों पर दबाव पड़ता है, जिससे अकाल, संघर्ष, गरीबी और बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, जब लोगों को दूषित जल ïतों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

शोधकर्ताओं की टीम ने जर्मन एयरोस्पेस सेंटर, जर्मन रिसचज़ सेंटर फॉर जियोसाइंसेज और नासा द्वारा संचालित ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट (जीआरएसीई) उपग्रहों के अवलोकनों का उपयोग करके दुनिया भर में मीठे पानी में अचानक आई कमी का पता लगाया है। जीआरएसीई उपग्रह मासिक पैमाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में उतार-चढ़ाव को मापते हैं जो जमीन पर और उसके नीचे पानी के द्रव्यमान में बदलावों को सामने लाते हैं।

अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया भर में मीठे पानी में गिरावट उत्तरी और मध्य ब्राजील में बड़े पैमाने पर सूखे के साथ शुरू हुई और इसके तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में बड़े पैमाने पर पड़े सूखे ने इसे आगे बढ़ाया।

2014 के अंत से 2016 तक उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र का बढ़ता तापमान, 1950 के बाद से सबसे बड़ी एल नीनो घटनाओं में से एक सामने आई, जिससे वायुमंडलीय जेट धाराओं में बदलाव आया जिसने दुनिया भर में मौसम और बारिश का पैटर्न को बदल दिया।

हालांकि अल नीनो के कम होने के बाद भी दुनिया भर में मीठे पानी में उछाल नहीं आया। जीआरएसीई द्वारा देखे गए दुनिया के 30 सबसे तीव्र सूखे में से 13 जनवरी 2015 से हुए हैं।शोधकताओज़ं का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग मीठे पानी की लगातार कमी के लिए जिम्मेवार हो सकती है।

नासा के गोडार्ड मौसम विज्ञानी ने कहा कि ग्लोबल वामिंज़्ग के कारण वायुमंडल में अधिक जल वाष्प जमा हो जाती है, जिसके कारण ज्यादा बारिश होती है। जबकि साल में होने वाली कुल बारिश और बर्फबारी के स्तर में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है, तीव्र बारिश की घटनाओं के बीच लंबी अवधि मिट्टी को सूखने और अधिक सघन होने देती है। इससे बारिश होने पर जमीन द्वारा अवशोषित किए जाने वाले पानी की मात्रा कम हो जाती है। जब भयंकर बारिश होती है, तो समस्या यह होती है कि पानी बह जाता है, बजाय इसके कि वह भूजल भंडार में समा जाए और उसे फिर से भर दे। दुनिया भर में 2014 से 2016 के अल नीनो के बाद से मीठे पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है, जबकि अधिक पानी जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में जमा है। तापमान बढ़ने से सतह से वायुमंडल में पानी का वाष्पीकरण और वायुमंडल की जल धारण करने क्षमता दोनों बढ़ जाती है, जिससे सूखे की स्थिति की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ जाती है।

पद्म श्री जीतकर देश के लिए मिसाल बने ये किसान

भारत सरकार हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर लोगों को उनके अनोखे योगदान के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करती है। 113 पद्म श्री पुरस्कार विजेताओं में से तीन जाने माने व्यक्तित्व जैसे हिमाचल प्रदेश के हरिमन शर्मा, नागालैंड के एल. हांगथिंग और महाराष्ट्र के सुभाष खेतुलाल शर्मा को कृषि के क्षेत्र में अनोखा योगदान देने के लिए पद्म श्री दिया गया।

इस साल भी केंद्र सरकार ने 76वें गणतंत्र दिवस से पहले की शाम पर शनिवार यानी 25 जनवरी 2025 को 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं. 113 पद्म श्री पुरस्कार विजेताओं में से तीन जाने माने व्यक्तित्व जैसे हिमाचल प्रदेश के हरिमन शर्मा, नागालैंड के एल. हांगथिंग और महाराष्ट्र के सुभाष खेतुलाल शर्मा को कृषि के क्षेत्र में अनोखा योगदान देने के लिए पद्म श्री दिया गया।

एल. हांगथिंग, फ्रूट मैन, पद्म श्री

नागालैंड के नोकलाक जिले के 58 साल के एल. हांगथिंग को बागवानी में उनके अद्भुत योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया। 30 सालों से ज्यादा के अनुभव के साथ, उन्होंने अपने क्षेत्र में लीची और संतरे जैसे फ्लों की खेती शुरू की। उनकी इस पहल से 40 से अधिक गांवों के 200 से अधिक किसानों को फायदा हुआ। हांगथिंग ने बचपन में ही अपने परिवार की जमीन पर फलों के बीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उनकी मेहनत और इनोवेटिव तरीकों को क्षेत्र के 400 से ज्यादा घरों ने इस्तेमाल करना शुरु कर दिया। उनके प्रयासों ने किसानों को नई फसलें उगाने और उनकी इनकम बढ़ाने में मदद की।

सुभाष खेतुलाल शर्मा, नेचुरल फार्मिंग, पद्म श्री

महाराष्ट्र के सुभाष खेतुलाल शर्मा ने टिकाऊ और ऑर्गैनिक खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1994 में केमिकल खेती के कारण उत्पादन में गिरावट देखने के बाद उन्होंने ऑर्गैनिक खेती अपनाई। उन्होंने गोबर, गुड़ और बारिश के पानी को रिजर्व करने जैसी तरीकों को अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने गांवों में टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल खेती का रास्ता दिखाया और कई किसानों को इस ओर प्रेरित किया। सुभाष यवतमाल से आते हैं। महाराष्ट्र का यह जिला किसानों की आत्महत्या के कारण चर्चा में रहा लेकिन इस जगह से आज एक किसान का पद्म श्री जीतना उम्मीद की किरण दिखाता है।

हरिमन शर्मा, सेब सम्राट, पद्म श्री

4 अप्रैल 1956 को हिमाचल प्रदेश के गिलासिन गांव में जन्मे हरिमन शर्मा का बचपन कठिनाईयों से भरा रहा. उनकी मां का निधन उनके जन्म के तीन दिन बाद हो गया था। उन्हें पन्याला गांव के श्री रिडकू राम ने गोद लिया। हरिमन ने बचपन से ही कृषि के बारे में सीखा। 1992 में उनके क्षेत्र में बर्फबारी से आम के पेड़ खराब हो गए, जिससे उन्होंने सेब की खेती का प्रयोग करने का फैसला किया, हालांकि सेब केवल ठंडे और ऊंचे क्षेत्रों में ही उगाए जाते थे।

हरिमन शर्मा की मेहनत और लगन ने 700 मीटर की ऊंचाई और 40°C से 45°C के टेम्परेचर में उगने वाले सेब की एक नई प्रजाति डिवेलप की। 2007 में उन्होंने HRMN-99 नाम के सेब की प्रजाति तैयार की, जो गर्म जलवायु में भी उगाई जा सकती है। HRMN-99 सेब की प्रजाति भारत के सभी 29 राज्यों और नेपाल, बांग्लादेश, जर्मनी जैसे देशों में उगाई जा रही है। हरिमन को नेशनल इनोवेटिव फामज़्र अवार्ड और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा ग्रासरूट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में 1 लाख से अधिक सेब के पौधे लगाए और किसानों को इसकी खेती सिखाई।

राष्ट्रीय बालिका दिवसः लड़कियों को सशक्त बनाने और उन्हें उचित अवसर दिए जाने की जरूरत

राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2008 में स्थापित यह दिवस बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा पर प्रकाश डालता है। भारतीय समाज में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालने के लिए हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पोषण तक समान पहुंच पर जोर देना है, साथ ही लड़कियों के साथ अक्सर होने वाले अन्याय को सामने लाना है। यह दिन लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र कल्याण के अधिकारों की वकालत करता है, एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। एक ऐसे देश में जहां लैंगिक असमानता, शिक्षा तक सीमित पहुंच, बहुत ज्यादा ड्रॉपआउट की दर, बाल विवाह और लिंग आधारित हिंसा बनी हुई है, इस पहल का महत्व और भी बढ़ जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य लड़कियों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को सामने लाना है, साथ ही भेदभाव से निपटने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र कल्याण के उनके अधिकारों की वकालत करता है, एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देने का प्रयास करता है जो हर बालिका का पोषण और समर्थन करता है। यह दिन लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र कल्याण के अधिकारों की वकालत करता है, एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह दिन लोगों को बाल विवाह जैसे बुरी प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रेरित करता है और लड़कियों को खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक सहायता हासिल करने में मदद करता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर लड़की को सशक्त, आत्मनिभज़्र और निपुण महिला बनने के समान अवसर मिलें। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 की थीम 'बेहतर भविष्य के लिए लड़कियों को प्रेरित करना' है। इस थीम में इस बात पर जोर दिया गया है कि लड़कियों को सशक्त बनाने और उन्हें उचित अवसर दिए जाने की जरूरत है। यह दिन लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र कल्याण के अधिकारों की वकालत करता है, एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। शिक्षा लड़कियों के लिए उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण मार्ग है। जब लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है और वे अच्छे स्कूलों में जाती हैं, तो वे नए कौशल हासिल करती हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की उनकी क्षमता बढ़ती है।

76वें गणतंत्र दिवस की सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं
सरपंच
शुशीला शिवराम सिंह भदोरिया
सचिव
सियासरण तिवारी
प्रधान प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत मछंड़ जनपद पंचायत रौन

76वें गणतंत्र दिवस की सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं
सरपंच
दयाल शरण खरे
रोजगार सहायक
ओपी लहरी
सचिव
रविन्द्र श्रीवास्तव
प्रधान प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत नौधा जनपद पंचायत रौन

76वें गणतंत्र दिवस की सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं
सरपंच
सवित्री देवी राजेश शर्मा
सचिव
अरुण कटारे
प्रधान प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत रारी शिकारपुरा

76वें गणतंत्र दिवस की सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं
सरपंच
मंगलेशवर सिंह (राजासाहब)
सचिव
निर्पत कुशवाह
सीएमओ
गोविंद सिंह
प्रधान प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत बोहारा मछरया

76वें गणतंत्र दिवस की सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं
सरपंच
आरती पुष्पेंद्र सिंह
सचिव
रघुराज सिंह
ग्राम पंचायत दवरेहा

76वें गणतंत्र दिवस की सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं
प्राचार्य
रोशन सिंह शाक्य
शा. हाईस्कूल बोनापुरा

76वें गणतंत्र दिवस की सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं
सहायक यंत्री
राजेश उपाध्याय
अध्यक्ष
सीएमओ
जनपद पंचायत रौन

76वें गणतंत्र दिवस की सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
सीएमओ
मिहोना नगर परिषद

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत सिजौरा जनपद पंचायत बल्देवगढ़

सरपंच श्री जयराम लोधी | रोजगार सहायक श्री दीपक कुमार पटेरिया | सचिव श्री पन्नालाल असाटी

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत मनपसार जनपद पंचायत बल्देवगढ़

सरपंच श्रीमती खुमनीबाई चढ़ार | रोजगार सहायक श्रीमती सुषमादेवी विश्वकर्मा | सचिव श्री भगीरथ लोधी

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत दुर्गानगर जनपद पंचायत बल्देवगढ़

सरपंच श्री विजय वंशकार | रोजगार सहायक श्री राकेश त्रिपाठी | सचिव श्री सत्यनारायण नायक

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत सुजानपुरा जनपद पंचायत बल्देवगढ़

सरपंच श्री उमराव अहिरवार | रोजगार सहायक श्री महेश जैन | सचिव श्री बालकिशन यादव

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत कंनपुर जनपद पंचायत बल्देवगढ़

सरपंच श्रीमती भागवती लोधी | सचिव श्री ग्यादीन लोधी | रोजगार सहायक श्री ब्रजबहादुर कुशवाहा

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत बृषभानपुरा जनपद पंचायत बल्देवगढ़

रोजगार सहायक श्री नंदकिशोर नायित | सरंपच श्रीमती प्रेमबाई वंशकार | सचिव श्री रामकिशन यादव

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत फरका पठराई जनपद पंचायत बल्देवगढ़

सरपंच श्रीमती जयंती-देवेन्द्र लोधी | रोजगार सहायक श्री खुमान लाल अहिरवार | सचिव श्री मुकेश तिवारी

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत बुदोरा जनपद पंचायत बल्देवगढ़

सरपंच श्रीमती विद्या लोधी | रोजगार सहायक श्री बंद्रीनाथ शुक्ला | सचिव श्री अलोक तिवारी

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत खजरार जनपद पंचायत बल्देवगढ़

सरपंच श्री अमर प्रताप सिंह | सचिव श्रीमती दीपा यादव | रोजगार सहायक श्री दीपा यादव

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत चंदेरी खास जनपद पंचायत बल्देवगढ़

सरपंच श्री रतिराम अहिरवार | सचिव श्री ग्यादीन लोधी

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत कोटरा जनपद पंचायत बल्देवगढ़

सरपंच श्रीमती मनीषा-श्रीराम यादव | सचिव श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत जटेरा जनपद पंचायत बल्देवगढ़

सरपंच श्रीमती भागवती सौर | सचिव श्री सत्यनारायण नायक | रोजगार सहायक श्री अवधेश कुमार मिश्रा

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत इमलिया जनपद पंचायत बल्देवगढ़

सरपंच श्रीमती फूल्लन प्रजापति | सचिव श्री संजय कांत प्रजापति | रोजगार सहायक श्री नन्हे भैया रजक

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत चौबारा जनपद पंचायत बल्देवगढ़

सरपंच श्रीमती मीराबाई प्रजापति | सचिव श्री सुन्दरलाल असाटी | रोजगार सहायक श्री मनोज कुमार विश्वकर्मा

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत लुहर्रा जनपद पंचायत बल्देवगढ़

सरपंच श्रीमती बेनीबाई प्रजापति | सचिव श्री हरिशंकर आदिवासी

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत रमपुरा जनपद पंचायत बल्देवगढ़

सरपंच श्री रामस्वरूप यादव | सचिव श्री जमना प्रसाद आदिवासी

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत देवीनगर जनपद पंचायत बल्देवगढ़

सरपंच श्री रामचरण अहिरवार | सचिव श्री संदीप यादव

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय थाना खरगापुर
जिला-टीकमगढ़ म.प्र.
थाना प्रभारी
श्री मनोज द्विवेदी

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय थाना कुड़ीला
जिला-टीकमगढ़ म.प्र.
थाना प्रभारी
श्री मनोज यादव

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत तालमऊ
जनपद पंचायत बल्देवगढ़
रोजगार सहायक श्री रजनेश राय
सरपंच श्री दिलीप सिंह लोधी
सचिव श्री अशोक कुमार रजक

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत चन्दपुरा
जनपद पंचायत बल्देवगढ़
सरपंच श्री विदेह पाठक
सचिव श्री रामदयाल यादव

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत इमलाना
जनपद पंचायत बल्देवगढ़
सरपंच श्रीमती बबली लोधी
सरपंच प्रतिनिधि राममिलन लोधी
सचिव श्री पुन्नेलाल अहिरवार

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत दोह
जनपद पंचायत बल्देवगढ़
सरपंच श्री महेश लोधी
सचिव श्री ओमप्रकाश पाण्डे

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

श्रीराम हर्षण स्टोनक्रेसर
मालिक श्री दुर्गा प्रसाद दीक्षित
श्री रामहर्षण तिवारी

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुड़ेरा
जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.)
बीएमओ
श्री शांतनु दीक्षित, डॉ. श्री रवि पुरोहित
दिलीप तिवारी एवं समस्त स्टाफ

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत पिपरा मड़ोरी जनपद पंचायत बल्देवगढ़

सरपंच श्रीमती सरोज राय
रोजगार सहायक श्री धर्मेन्द्र पटेरिया
सचिव श्री राजेन्द्र यादव

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत बरमे
जनपद पंचायत बल्देवगढ़
सरपंच श्रीमती भूरीबाई लोधी
सचिव श्री गनेश अहिरवार

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय नगर परिषद खरगापुर
जिला-टीकमगढ़ म.प्र.

अध्यक्ष- कु.दीप्ति कोरी
आर एस- अवास्थी
लेखापाल- शिवम मिश्रा

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत धानेरा
जनपद पंचायत बल्देवगढ़
सरपंच श्रीमती भागवती अहिरवार
सचिव श्री रामरतन अहिरवार
रोजगार सहायक श्री ग्यादीन अहिरवार

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत गुखरई खास
जनपद पंचायत बल्देवगढ़
सरपंच श्रीमती रुपरानी लोधी
सचिव श्री भागीरथ प्रसाद यादव
रोजगार सहायक श्री शिशुपाल लोधी

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत जिनागढ़
जनपद पंचायत बल्देवगढ़
सरपंच श्रीमती शीलू दुबे
सचिव श्री भरतलाल मिश्रा

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

कार्यालय ग्राम पंचायत लडवारी खास
जनपद पंचायत बल्देवगढ़
सरपंच श्रीमती भागवती लोधी
सचिव श्री बाबूलाल लोधी

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

एमएस कंस्ट्रक्शन कंपनी
ठेकेदार
श्री वीरेन्द्र गुप्ता

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

तपस्या कंस्ट्रक्शन पलेरा
ठेकेदार
श्री रानू तिवारी

गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐ

मे. डिवाइन मिनरल्स स्टोन क्रेशर
परसुआ ग्राम पंचायत प्रेमपुरा
संचालक
मोइन खान

इन्वेस्ट मध्यप्रदेश
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट
अनंत संभावनाएँ
24-25 फरवरी 2025, भोपाल

76वें
गणतंत्र दिवस
की प्रदेशवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं

संवैधानिक मूल्यों के साथ
मध्यप्रदेश का चौतरफा विकास

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (GYAN) समाज के इन चार स्तंभों के सशक्तिकरण की
मजबूत बुनियाद पर मध्यप्रदेश छुएगा विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयां

गरीब कल्याण मिशन के माध्यम से प्रदेश के गरीब और वंचितों को मिलेंगे आगे बढ़ने के हर संभव अवसर। वर्ष 2028 तक प्रदेश बनेगा गरीबी मुक्त।

स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, रोज़गार और नेतृत्व क्षमता विकास से सुनिश्चित करेगा युवाओं का सशक्तिकरण।

देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन महिलाओं के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करेगा।

किसान कल्याण मिशन के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार किसानों की आय वृद्धि के साथ ही कृषि को अधिक लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए समर्पित है।

सीधा प्रसारण @Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh @Cmmadhyapradesh @JansamparkMP JansamparkMP

D-18068/24

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। **संपादकः** अजय कुमार द्विवेदी, **स्थानीय संपादकः अरविंद मिश्रा, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)